निर्यात बढ़ाने की तैयारी करने वाले राज्यों में यूपी अब चौथे स्थान पर

नीति आयोग ने जारी किया चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक महाराष्ट्र अग्रणी, भूमि से घिरे राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। निर्यात बढ़ाने के लिए सभी तैयारियां करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष-5 बड़े राज्यों में जगह बनाते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही, भूमि से घिरे (लैंड लॉक्ड) राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर सातवें और भूमि से घिरे राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा था।

नीति आयोग की ओर से बुधवार को जारी चौथे निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2024 में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर काबिज हैं।

नीति आयोग की ओर से जारी सूचकांक राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के संदर्भ में उनकी तैयारियों के आकलन के लिए बनाया गया है। इसमें शीर्ष-10 बड़े राज्यों में कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और हरियाणा भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

नीति आयोग के सीईओ बीवी आर सुब्रह्मण्यम ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौतों के विस्तार के साथ ही मजबूत घरेलू आधार का महत्व बढ़ता जा रहा है। राज्यों के लिए इसका अर्थ ऐसे परिवेश को बढ़ावा देना है, जो नए अवसर पैदा कर सके और जिलों में भी प्रतिस्पर्धी माहौल बना सकें।

छोटे राज्यों में उत्तराखंड सबसे आगे

निर्यात के लिए तैयारियां करने में छोटे राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा और त्रिपुरा का स्थान है।

- शीर्ष-10 छोटे प्रदेशों में असम, पुडुचेरी और चंडीगढ़ भी शामिल। दिल्ली 29वें और हिमाचल प्रदेश 30वें स्थान पर।

मूल्यांकन के चार प्रमुख आधार

निर्यात तैयारी सूचकांक में एक सुसंगत एवं आंकड़ा आधारित पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। **इसके तहत चार प्रमुख आधारों निर्यात नीतियों, कारोबारी माहौल, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता एवं निर्यात प्रदर्शन पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया है।**

इसमें सबसे ज्यादा कारोबारी माहौल पर जोर दिया गया है, जिसकी मूल्यांकन में हिस्सेदारी 40 फीसदी है। इसके बाद निर्यात नीतियों, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और निर्यात प्रदर्शन का हिस्सा 20-20 फीसदी है।

- इसमें आंकड़े राज्य और केंद्र सरकार दोनों के स्रोतों से जुटाए जाते हैं। हर संकेतक को उसके महत्व के आधार पर भार प्रदान किया जाता है।